

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-13/2014

द्रोपदी बंसल पत्नी श्री लेखराज बंसल (मृतक दौराने अपील)

1/1 लेखराज बंसल पुत्र श्री गंगाराम बंसल

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, निदेशालय, बीकानेर।
3. उप निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, अजमेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, अजमेर।
5. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर।

—प्रत्यर्थागण

आदेश की दिनांक : 14.05.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेश राज कुमावत, अभिभाषक
प्रत्यर्था विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपीलार्थीया (द्रोपदी बंसल) की मृत्यु हो जाने के कारण अपीलार्थीया के पति श्री लेखराज बंसल विधिक उत्तराधिकारी होने के नाते इस अपील को आगे चलाना चाहते हैं और उक्त अपील को गुणावगुण के आधार पर निस्तारित करना चाहते हैं।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अपीलार्थीया द्रोपदी बंसल की मृत्यु हो जाने के पश्चात अपीलार्थीया के स्थान पर उनके पति लेखराज बंसल को लगायत 1/1 के रूप में पक्षकार बनाया जाता है।
3. अपीलार्थीया ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थीया की नियुक्ति आदेश दिनांक 26.10.1976 के द्वारा अध्यापिका के रूप में हुई थी। अपीलार्थीया ने दिनांक 28.10.1976 को कार्य भार ग्रहण किया। इसके पश्चात सेवा में रहते हुए अपीलार्थीया दिनांक 22.06.1977 को बीएसटीसी कर प्रशिक्षित अध्यापिका बन गई।

4. अपीलार्थीया का चयन नियमानुसार हुआ था तथा वह अपनी नियुक्ति तिथी से ही नियमित कर्मी रही है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीया को आदेश दिनांक 25.01.1992 के अनुसार चयनित वेतनमान का लाभ उसकी प्रथम नियुक्ति तिथी से सेवा की गणना कर दिया जाना चाहिये था किन्तु उसे मनमानेतौर पर उक्त लाभ प्रशिक्षण पूर्ण करने की दिनांक से लाभ प्रदान किये गये हैं, जो कि अपीलार्थीया प्रथम नियुक्ति दिनांक 28.10.1976 से सेवा की गणना कर प्राप्त करने की नियमानुसार अधिकारीणी है। अपीलार्थीया अपनी अधिवाषिकी आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.05.2009 को सेवानिवृत्त हो चुकी है तथा उसने चयनित वेतनमान का लाभ प्रथम नियुक्ति तिथी से सेवा की गणना कर दिलवाये जाने हेतु कई बार अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किये किन्तु किसी प्रकार की कार्यवाही प्रत्यर्थीगण द्वारा नहीं की गई।

5. उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है :-

"अतः अपील प्रस्तुत कर सादर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीया व्यय सहित स्वीकार फरमाई जावे तथा प्रत्यर्थीगण को आदेशित फरमाया जावे कि वे अपीलार्थीया को चयनित वेतनमान का समस्त लाभ उसकी प्रथम नियुक्ति तिथी 28.10.1976 से सेवा की गणना कर प्रदान करे तथा बकाया एरियर का भुगतान करे। तदनुसार नियमानुसार मिलने वाले अन्य सभी लाभ परिलाभ जो अपीलार्थीया को प्रथम नियुक्ति से सेवा की गणना कर चयनित वेतनमान का लाभ मिलने के उपरांत प्राप्त होते हो वे सभी लाभ परिलाभ अपीलार्थीया को प्रदान करने हेतु प्रत्यर्थीगण को आदेशित फरमाया जावे।

अन्य अनुतोष जो अपीलार्थीया के पक्ष में माननीय अधिकरण उचित समझ वे भी अपीलार्थीया को प्रदान फरमाये जावे।"

6. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी की नियुक्ति पंचायत समिति डिडवाना द्वारा जारी आदेश 26.10.1976 में उल्लेखित शर्तों के तहत अध्यापिका के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय बालिका धनकोली में हुई चूंकि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अप्रशिक्षित अध्यापक के पद पर हुई। अपीलार्थीया 10 वर्ष की सेवा के पश्चात् शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता अन्तर्गत माना गया है। प्रार्थनी ने बीएसटीसी परीक्षा 22.06.1977 को अर्जित की है। वर्णित तथ्यों के तदनुसार ही वह नियमितकरण की हकदार है। उक्तानुसार वह सेवा संबंधित लाभ प्राप्ति की अधिकारी है।
7. हमने दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

8. अपीलार्थीया के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थीया को चयनित वेतनमान का लाभ उसकी सेवा की गणना उसकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक 28.10.1976 न करके उसके द्वारा बीएसटीसी उत्तीर्ण करने की दिनांक 22.06.1977 से सेवा की गणना करते हुए दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 589/2015 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रा राम में पारित तीन न्यायाधिपति की पीठ के निर्णय दिनांक 03.07.2017 का अवलोकन करें तो उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न बिन्दुओं पर अपना निर्णय दिया है :-

- "(a) Whether the respondents stand regularized from the date of appointment after scrutiny by the District Establishment Committee?
 (b) Whether their order of regularization is still valid or has been annulled?
 (c) Whether the appellants can assail the order of regularization without having actually annulled it till today?
 (d) Whether there can be two dates for regularization of an employee, retrospective for some purposes and prospective for others?
 (e) Does Goparam (supra) lay down the correct law in distinguishing Jagdish Narain Chaturvedi (supra) and Surendra Mohnot (supra)?"

उपरोक्त बिंदुओं पर माननीय उच्च न्यायालय से निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है :-

37. QUESTION A For the reasons and discussions aforesaid and in view of the law declared by the Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi and Surendra Mahnot & Ors. (supra); we are of the opinion that the respondent - employee would stand regularized from the date of regularization in service and not prior to that.

38. QUESTION B Taking into consideration the recent decision, prior to two decades the regularization period was not questioned by anybody, therefore, in a writ petition filed by the petitioner it will not be appropriate for us to allow the Government to end the regularization. However, regularization will be from the date of regularization done by the department and not prior thereto.

39. QUESTION C The contention of the counsel for the employees is required to be accepted and it cannot be annulled unless it has been annulled by appropriate authority. However, the benefits shall not be withdrawn but in future when the benefits are to be accorded for further promotion, the same will be considered on the basis of new law declared by the Supreme Court i.e. period will be considered from the date of regularization. When the future benefit of 9, 18 and/or 27 will be considered their ad-hoc service will not be considered for the purpose of benefit of 9, 18 and/or 27 years. But if benefit has already been granted for all the three scales; the same shall not be withdrawn and no recovery will be made from the employees.

40. QUESTION D In view of our answer in above matters, it is very clear that for the purpose of regularisation the date of regularisation will be from the date of regular appointment. In that view of the matter, there cannot be two dates for the purpose of

seniority and the other benefits. However, earlier services will be considered for the purpose of the same if there is a shortage in pensionary benefits.

41. QUESTION E In view of the observations made by the Supreme Court, as referred to above, the ad-hocism will not be considered for seniority. In that view of the matter, there will be only one date for regularization, date of regularizing ad-hoc period will not have any effect on seniority. In our considered opinion, the Division Bench of this Court in the case of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram in DB Civil Special Appeal No.44/2016, decided on 18.04.2016 had no right to distinguish the judgment of the Supreme Court in the case of Jagdish Narayan Chaturvedi (Supra) and State of Rajasthan vs. Surendra Mohnot & Ors. (supra). Thus, the decision of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram (supra) did not lay down correct law. The correct law would be the law declared by the Supreme Court in the two judgments referred hereinabove.

9. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना है कि नियमितिकरण की दिनांक से ही कार्मिक को चयनित वेतनमान का लाभ दिया जा सकता है। इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 27644/2018 बीना शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 21.12.2018 में बीएसटीसी प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने के पश्चात ही एसीपी का लाभ दिया जाना उचित माना है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थीया ने बीएसटीसी प्रशिक्षण दिनांक 22.06.1977 को पूर्ण किया था, तभी से अपीलार्थीया की नियमित नियुक्ति होना माना जा सकता है। अतः अपीलार्थीया पूर्व की सेवाओं को चयनित वेतनमान के लाभ के लिये नहीं जुड़वा सकती है।
10. परिणामस्वरूप अपीलार्थीया की अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)